Capacity of Foodgrains Storages in the Country

1539. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) the capacity-wise details of Government stores in the country ;

(b) whether it is a fact that Government foodgrain stores have no money and space to purchase and store more foodgrains ; and

(c) if so, whether private agriculturists who have money and storage facility for foodgrains will be allowed to store and export foodgrains in the liberalized economy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) The capacity-wise details of the total storage capacity available with Food Corporation of India for storage of foodgrains as on 1-11-1994 was as under :—

(in lakh tonnes)

	Covered	CAP (Cover and Plinth)
Owned	122.61	14.22
Hired	93.80	36.43
TOTAL :	216.41	50.65

(b) No, Sir.

(c) There are no stock limits for storage of foodgrains by farmers and they can export foodgrains according to the existing export policy in which export of wheat, rice, coarse-grains and pulses is allowed within fixed quantitative ceilings.

मध्य प्रदेश में चीनी एककों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाना

1540. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले नए चीनी एककों को केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आवधिक ऋण देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां तो किन-किन वित्तीय संस्थाओं को आवधिक ऋण संबंधी आवेदन पत्रों के संबंध में कार्यवाही करने को कहा गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इन संस्थाओं ने अब तक ऐसे कितने प्रस्तावों पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) वित्तीय संस्थाएं खुद ही नई चीनी इकाईयों को उनकी व्यवहार्यता और उपलब्ध फण्ड के आधार पर आवधिक ऋण उपलब्ध करा रही हैं ।

(ख) और (ग) नई चीनी फैक्ट्रियों को आवधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाएं हैं— आई. एफ. सी. आई., आई डी. पी. आई., आई. सी. आई. सी. आई. और आई. आर. बी. आई. ।

(घ) और (ङ) आई. एफ. सी. आई. द्वारा 1993-94 वर्ष के दौरान भेजी गई सूचना के अनुसार आई. एफ. सी. आई. ने मध्य प्रदेश में नर्मदा शूगर्स लि. को 1000 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था ।

दक्षिणी गुजरात में चीनी मिलों के विस्तार हेतु ऋण प्रदान किया जाना

1541. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दक्षिणी गुजरात स्थित चीनी मिलों के विस्तार हेतु ऋण को मंजूरी देने के संबंध में गुजरात राज्य सरकार से कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मिल के विस्तार हेतु वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार और वित्तीय संस्थाएं कब तक ऋण उपलब्ध करवा देंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) चीनी विकास निधि से